जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 19 संख्याः 358 प्रभात जालोर, रविवार 6 अप्रैल, 2025 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

कांग्रेस अधिवेशन के लिये तैयार प्रस्ताव में भाजपा पर जमकर ''अटैक'' किया गया है

प्रस्ताव के अनुसार, भाजपा व संघ परिवार ने मुसलमानों को अपना लक्ष्य बना रखा है, सनातन धर्म व हिन्दुत्व के एजेण्डा की ओर जनता को ध्रुवीकृत करने के लिये

- कांग्रेस के प्रस्ताव में मोदी सरकार की तीखी आलोचना इस मुद्दे पर की गई है कि मोदी सरकार ने अमेरिका व राष्ट्रपति ट्रम्प के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है, टैरिफ के मुद्दे पर।
- मोदी सरकार को इस बात के लिये दोषी बताया गया है कि वह चीन से मित्रता व भाईचारा बढ़ा रही है, जबकि चीन ने अभी भी भारत की 4000 किलोमीटर जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है।
- यह प्रस्ताव 8 अप्रेल को अहमदाबाद कांग्रेस की ''एक्सटैंडेड सी.डब्ल्यु.सी. (वृहत् कार्यकारिणी) में पेश होगा। इस सी.डब्ल्यु.सी. में 169 नेता भाग लेंगे तथा कांग्रेस में पुनः जोश डालने के लिये तैयार रणनीति पर भी विचार होगा।
- महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के सौ वर्ष पूरे होने पर तथा वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्मतिथि को स्मरण करने के लिए, कांग्रेस का यह अधिवेशन गुजरात में आयोजित किया गया है।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 अप्रेल। आठ और नौ अप्रेल को होने वाले ए.आई.सी.सी. अधिवेशन के लिए मसौदा समिति द्वारा प्रस्ताव में कांग्रेस की विचारधारा को महत्व दिया गया है तथा भाजपा और संघ परिवार की विभाजनकारी और असंवैधानिक विचारधारा से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

प्रस्ताव में भाजपा और संघ परिवार पर तीखा प्रहार किया गया है तथा सनातन व हिंदुत्व एजेंडा को और अधिक मजबूत करने के लिए भाजपा व संघ द्वारा अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के प्रयासों पर भी हमला किया गया है।

मसौदा समिति के सदस्य, एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा कि, भारत पर लगाए जाने वाले प्रस्तावित टैरिफ के मामले में अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप का मुकाबला नहीं करने के लिए मोदी सरकार पर भी तीखा आक्रमण किया गया है।

इसी के साथ, मोदी सरकार के चीन के साथ दोस्ताना संबंधों पर भी तीखा हमला किया गया है, खासकर इस तथ्य के मद्देनज़र कि चीन ने भारत की 4000 किलोमीटर से अधिक भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है।

सन् 2024 के लोकसभा चुनावों में 99 लोकसभा सीटें जीतने के बाद हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र में पार्टी की हार के मद्देनज़र पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए कांग्रेस को एक रोडमैप

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में बाबूलाल कटारा और सहारण को जमानत नहीं

जयपुर, 5 अप्रैल। सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 के पेपर लीक मामले में आरपीएससी के सदस्य रहे बाबूलाल कटारा और एक अन्य आरोपी गोपाल सहारण की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया है। पीठासीन अधिकारी सूनील रणवाह ने

- सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने आरपीएससी के पूर्व सदस्य कटारा तथा एक अन्य आरोपी की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया।

अपने आदेश में कहा कि सार्वजनिक परीक्षाओं के पेपर लीक होने से समाज पर गहरा प्रभाव पडता है। ऐसे में आरोपियों को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

जमानत अर्जी में आरोपी बाबूलाल कटारा ने कहा कि उसे मात्र शंका के आधार पर मामले में आरोपी बनाया गया है। प्रश्न पत्र से संबंधित कोई भी सामग्री उससे बरामद नहीं हुई है। इसके अलावा जिस बस में अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र पढवाया जा रहा था, वह वहां भी मौजूद नहीं था। इसके साथ ही अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य भी नहीं है। वह 65 साल का वृद्ध है और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'जो भूमि ''गैर कानूनी'' तरीके से वक्फ की सम्पत्ति घोषित की गई है, उसे सरकार अपने कब्जे में ले'

योगी आदित्यनाथ सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पारित होते ही, अपने जिलाधीशों को आदेश दिये

- यू.पी. सरकार के अनुसार, रैवेन्यु रिकॉर्ड्स के अनुसार, राज्य में 2963 प्रॉपर्टीज हैं, वक्फ बोर्ड के पास। परन्तु, वक्फ बोर्ड के रजिस्टर 37 के अनुसार, सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 1,24,355 प्रॉपर्टी हैं तथा शिया वक्फ बोर्ड के पास 7,785 प्रॉपर्टी हैं।
- अतः यू.पी. सरकार अब उन सब प्रॉपर्टीज को अधिकृत करना चाहती है, जो रैवेन्यु बोर्ड के रिकॉर्ड के अनुसार, वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति के रूप में दर्ज नहीं हैं।
- यू.पी. सरकार ने सभी जिलाधीशों को निर्देशित किया है कि अपने जिले में उन सभी सम्पत्तियों को चिन्हित करें, जिन्हें ''गैर-कानूनी'' तरीके से वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति घोषित कर रखा है।
- सरकार की परिभाषा के अनुसार, वो ही सम्पत्ति वक्फ बोर्ड की हो सकती है, जो बोर्ड को दान के रूप में मिली हो तथा ग्राम, समाज व सरकार की भूमि को वक्फ बोर्ड की भूमि नहीं माना जा सकता।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 अप्रैल। वक्फ संशोधन बिल पारित होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार एक्शन में आ गई है। मुख्यमंत्री ने अवैध रुप से घोषित वक्फ संपत्तियों को जब्त करने के आदेश दे दिए हैं। यूपी सरकार का दावा है कि सरकार के राजस्व रिकॉर्ड में सिर्फ 2963 भूखंड ही वक्फ के तहत रजिस्टर्ड हैं। जबकि रजिस्टर 37 के अनुसार सुन्नी वक्फ बोर्ड की लिस्ट में 1,24,355 सम्पत्तियां हैं और शिया वक्फ बोर्ड लिस्ट में 7,785 संपत्तियां दर्ज हैं। आंकड़ों की विसंगति को देखकर राज्य सरकार ऐसी सभी वक्फ संपत्तियां जब्त करने की तैयारी में है, जिसका रैवेन्यु रिकॉर्ड में उल्लेख नहीं है।

हालिया आदेश में रैवेन्यु विभाग ने सभी जिलाधीशों को निर्देश दिया है कि ऐसी सम्पत्तियों को चिन्हित किया जाए जिन्हें अवैध रुप से वक्फ सम्पत्ति घोषित कर रखा है। सरकार की परिभाषा के अनुसार वक्फ सिर्फ दान की गई सम्पत्तियों पर ही लागू हो सकता है। सरकार की या ग्राम समाज की जमीन को वक्फ की सम्पत्ति घोषित नहीं किया जा सकता।

इसी बीच वक्फ बनाम कैथलिक चर्च की जमीन पर भी विवाद उठ रहा है। आरएसएस के एक प्रकाशन ''ऑर्गनाइज़र'' में हाल ही में एक लेख छपा है जिसमें वक्फ बोर्ड और कैथलिक चर्चों की जमीनों को एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया। लेकिन आनन फानन में इस आलेख को हटा लिया गया। इस घटनाक्रम ने राहुल गांधी व अन्य विपक्षी नेताओं को संसद

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'सरकार के बाद, सबसे ज्यादा ज़मीन ईसाई धार्मिक संस्थाओं के पास है'

संघ के मुख पत्र ''ऑर्गनाइज़र'' में छपे एक लेख के अनुसार, भारत में ईसाई धार्मिक संस्थाओं के पास 7 करोड़ हैक्टेयर भूमि है, जिसकी कीमत बीस हजार करोड़ रूपये मानी जा सकती है

- हालांकि, द ऑर्गनाइज़र ने इस लेख को बाद में अपनी पत्रिका से निकाल दिया (विड्रॉ कर लिया) पर, यह ''अप्रकाशित'' लेख काफी राजनीतिक बहसों में मुख्य मुद्दा बना रहा।
- राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने संसद में बहस के दौरान भी कहा था कि वक्फ संशोधन विधेयक पारित करके, भाजपा ने अल्पसंख्यकों को टारगैट करने का रास्ता साफ कर लिया है और अब दूसरा टारगैट ईसाई होंगे। राहुल ने शनिवार को यह आशंका, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर पुनः दोहरायी, संसद में भाषण का उल्लेख करते हुए।
- राहुल ने यह भी कहा, इस संदर्भ में, कि संविधान ही एक ढाल है, जो हमारे अल्पसंख्यकों को, इस ''अटैक'' से बचा सकता है।

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 अप्रेल। लोकसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज आरोप लगाया कि संसद द्वारा पारित वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ है और यह भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने की मिसाल बनेगा।

एक्स पर एक पोस्ट में राहुल ने एक आलेख शेयर कर दावा किया कि अब संघ की नज़रें कैथलिक चर्च की जमीनों पर हैं।

उन्होंने कहा कि, मैंने कहा था वक्फ बिल अभी मुसलमानों पर वार है, पर, भविष्य में यह अन्य समुदायों को निशाना बनाने के लिए नज़ीर बनेगा। संघ को ईसाईयों की ओर फोकस करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उन्होंने लिखा, ''संविधान ही एकमात्र ढाल है, जो हमारे लोगों को ऐसे हमलों से बचाता है। यह हमारा सामुहिक कर्तव्य है कि हम इसकी रक्षा करें।''

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कोटा में छात्रा ने फाँसी लगाकर आत्महत्या की

कोटा, 5 अप्रैल (निसं)। बोरखेड़ा थाना इलाके में एक छात्रा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कहा जा रहा है कि आत्महत्या का कारण पढ़ ाई को लेकर डिप्रेशन हो सकता है। घटना के समय छात्रा घर में अकेली थी।

बोरखेड़ा थाने के एएसआई मोहम्मद हुसैन ने बताया कि प्रगति नगर निवासी छात्रा प्रतिष्ठा उर्फ ट्विंकल (17) ने घर में फांसी

- छात्रा 11वीं कक्षा के साथ ही नीट की तैयारी भी कर रही थी।

लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की बड़ी बहन ने बताया कि उसकी बहन पढ़ाई के कारण तनाव में थी।

बोरखेडा थानाधिकारी देवेश भारद्वाज ने बताया कि मृतका छात्रा 11वीं कक्षा के साथ-साथ नीट की पढ़ ाई कर रही थी।

वर्तमान में वह किसी कोचिंग संस्थान की छात्रा नहीं थी। उन्होंने बताया कि घटना के समय मां दूध लेने गई थी और बड़ी बहन लाईब्रेरी में पढ़ ने गई थी। पिता कोटा से बाहर जॉब करते हैं। पिता को भी घटना की सूचना दे दी गई है।

नई टैक्सटाइल पॉलिसी में स्टांप ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी

अमेरिकी टैरिफ के बाद बदलते वैश्विक परिदृश्य में यह नीति वस्त्र निर्यातकों के लिये गेम चेन्जर साबित होगी

- अमेरिका द्वारा भारतीय कपड़े के आयात पर लगाया टैरिफ बाँग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, पाकिस्तान व चीन की तुलना में कम है। यह अमेरिका को वस्त्र निर्यात बढ़ाने के लिये अनुकूल साबित हो सकता है।

जयपुर, 5 अप्रेल। मुख्यमंत्री भजनलाल ने प्रदेश में 'राजस्थान टेक्सटाइल एण्ड अपैरल पॉलिसी-2025' लागू की है। अमेरिका द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किए जाने के बाद बदलते वैश्विक परिदृश्य में राजस्थान के वस्त्र निर्यातकों के लिए यह नीति गेम चेंजर भी साबित होने जा रही है।

नई राजस्थान टेक्सटाइल एवं अपैरल पॉलिसी के तहत वस्त्र व परिधान क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 10 वर्षों तक 80 करोड़ रूपये वार्षिक तक का एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, भूमि/भवन क्रय या लीज पर स्टांप ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट, बिजली उपभोग पर 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी छूट प्रदान की जाएगी। वहीं पर्यावरणीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस नीति में ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के तहत 12.5 करोड़ रूपये तक 50 प्रतिशत, अक्षय ऊर्जा संयंत्रों के लिए बैंकिंग, व्हीलिंग व ट्रांसमिशन शुल्क का 100 प्रतिशत, पेटेंट/कॉपीराइट लागत का 50 प्रतिशत एवं भूमि रूपांतरण शुल्क का 100 प्रतिशत पुनर्भरण के प्रावधान किए गए हैं। इसी तरह निर्यात इकाइयों को फ्रेट चार्ज पर 25 प्रतिशत तथा कार्मिक प्रशिक्षण लागत का 50 प्रतिशत पुनर्भरण का प्रावधान किया गया है। हाल ही में अमेरिका द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाने के बाद वैश्विक स्तर पर आर्थिक परिदृश्य लगातार बदलावों से गुजर रहा है। भारतीय कपड़ा आयात पर लगभग 27 प्रतिशत पारस्परिक (त्मबपचतवबंस) टैरिफ अमेरिका द्वारा लगाया गया है जो इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी देशों जैसे बांग्लादेश (37 प्रतिशत), वियतनाम (46 प्रतिशत), कंबोडिया (49 प्रतिशत), पाकिस्तान (29 प्रतिशत) और चीन (34 प्रतिशत) की तुलना में कम है। राजस्थान देश का चौथा सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है और यहां भीलवाड़ा, जयपुर, पाली एवं बालोतरा जैसे टेक्सटाइल हब के वस्त्र निर्माताओं के लिए लंबी अवधि में यह स्थिति अमेरिका को वस्त्र निर्यात बढ़ ाने के लिए अनुकूल साबित हो सकती है। राजस्थान में टेक्सटाइल और गारमेंट क्षेत्र से जुड़े कुशल कार्यबल की भी पर्याप्त उपलब्धता है। इस परिदृश्य में प्रदेश में लागू की गई टेक्सटाइल एवं अपैरल पॉलिसी-2025 उद्यिमयों एवं निर्यातकों के लिए सोने पर सुहागा साबित होगी। इस नीति का उद्देश्य आधुनिक अवसंरचना एवं तकनीकी उन्नयन के माध्यम से टेक्सटाइल वैल्यू चेन को मजबूती देना है। नीति के अंतर्गत समावेशी विकास पर विशेष ध्यान देते हुए इस क्षेत्र में 10 हजार करोड़ रूपये के निवेश तथा 2 लाख रोजगार के सृजन पर भी जोर दिया गया है। इस नीति के माध्यम से 5 नए टेक्सटाइल पार्क विकसित करने के साथ ही, नई व विस्तारित हो रही परिधान निर्माण इकाइयों को सहायता दी जाएगी।

यह नीति प्रदेश में टेक्सटाइल एण्ड अपैरल क्षेत्र के सतत् व समग्र विकास के साथ-साथ इस क्षेत्र में रोजगार सृजन, कौशल विकास, नवाचार, उत्पादकता और निर्यात को बढ़ ावा देगी। वहीं दूसरी ओर इससे वैश्विक स्तर पर स्थानीय वस्त्र उत्पादकों की दक्षता और विश्वसनीयता में वृद्धि के साथ ही, प्रदेश में परिधान (अपैरल) उद्योग के एक नये दौर की शुरूआत होगी।

सफल आवंटियों को भूखण्ड नहीं देने पर अवमानना नोटिस

जयपुर, 5 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बाद भी सफल आवंटियों को पृथ्वीराज नगर योजना में भूखंड नहीं देने पर प्रमुख नगरीय विकास सचिव वैभव गालरिया व जेडीसी आनंदी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस

- हाई कोर्ट के, भूखण्ड का पट्टा देने के आदेश की पालना नहीं होने पर अवमानना कार्यवाही की जा रही है।

नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश डॉ. आरएन अग्रवाल व अन्य की अवमानना याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता राकेश कुमार ने बताया कि याचिकाकर्ता पृथ्वीराज नगर योजना के सफल आवंटी हैं। उन्होंने जेडीए के 15 सितंबर 2006 के आदेश की पालना में भूखंड

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

माइक्रोसॉफ्ट की पचासवीं सालगिरह पर आयोजित उत्सव में फिलिस्तीन समर्थक नारों ने भारी विघ्न डाला

उत्सव समारोह में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, बिल गेट्स, पूर्व सी.ई.ओ. स्टीव बाल्मर व वर्तमान सी.ई.ओ. सत्य नडेला भी मौजूद थे

- महिला टैकी, इब्तिहाल अबूसाद व वनिया अग्रवाल ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि माइक्रोसॉफ्ट के टैक्निकल स्टाफ के हाथ खून से रंगे हैं। क्योंकि, इज़रायल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ए.आई. सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल चिन्हित बम्बारी के लिये कर रहा है तथा पचास हजार व्यक्ति मारे गये हैं।
- पहले तो माइक्रोसॉफ्ट ने इस घटना के बारे में कहा कि हम हमारे सभी कर्मचारियों को अपनी बात कहने का पूरा अवसर देते हैं। पर, साथ ही यह भी कहते हैं कि अपनी बात इस तरह कहें कि कम्पनी का ''बिज़नैस'' प्रभावित न हो। अगर बिज़नेस प्रभावित होता है तो हम उस कर्मचारी को अन्यत्र नौकरी करने का विकल्प देते हैं।
- जब इब्तिहाल अबूसाद व वनिया अग्रवाल घर पहुँचीं तो उन्होंने पाया कि वो अपना कम्पनी वर्क एकाउंट नहीं खोल पा रही हैं, उनके विरोध प्रदर्शन के बाद। यह इस बात का संकेत था कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है।

-डा. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 अप्रैल। इस सप्ताह शुक्रवार को कंपनी की 50 वीं वर्षगांठ के समारोह में माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों ने फिलिस्तीन के समर्थन में विद्रोह किया, जो आई.टी. पेशेवरों में इज़रायल के खिलाफ तीव्र आक्रोश को दर्शाता है। यह विरोध प्रदर्शन समारोह में कंपनी के सह संस्थापक बिल गेट्स और पूर्व सी.ई.ओ. स्टीव बाल्मर भी उपस्थिति में हुआ। तकनीकी उद्योग द्वारा इज़रायली मिलिटरी को आर्टिफिशल इन्टैलिजैंस (ए.आई.) सप्लाई करने को लेकर यह नवीनतम विरोध, अमेरिका में फैली इज़रायल विरोधी गहरी भावनाओं को उजागर करता है।

यह विरोध उस समय शुरु हुआ जब माइक्रोसॉफ्ट ए.आई. के सी.ई.ओ. मुस्तफा सुलेमान प्रॉडक्ट अपडेट्स तथा कम्पनी के ए.आई. प्रॉजडक्ट, ''कैपिटल'' के लिए दीर्घकालीन दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे थे। इस दौरान माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स और पूर्व सी.ई.ओ. स्टीव बाल्मर भी उपस्थित थे।

माइक्रोसॉफ्ट की कर्मचारी इब्तिहाल अबूसाद ने मंच की तरफ जाते हुए चिल्लाकर कहा, ''मुस्तफा तुम्हें शर्म आनी चाहिए।'' यह सुनकर सुलेमान ने अपना भाषण रोक दिया।

कर्मचारी ने कहा, ''तुम दावा करते हो कि तुम ए.आई. का अच्छा उपयोग करना चाहते हो, लेकिन, माइक्रोसॉफ्ट इज़रायल को ए.आई. हथियार बेचता है। पचास हज़ार लोगों की मौत हो चुकी है और माइक्रोसॉफ्ट हमारे क्षेत्र में इस नरसंहार को संभव बना रहा है।''

सुलेमान ने कहा, ''आपके विरोध

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रामनवमी पर शुभकामनाएं दीं

जयपुर, 5 अप्रेल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रामनवमी के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

शर्मा ने कहा कि भगवान श्रीराम का जीवन हम सभी के लिए अनुकरणीय है। उनका जीवन त्याग, सेवा, वचनबद्धता और कत्तर्व्यनिष्ठा का ऐसा अनुपम उदाहरण है, जो सम्पूर्ण जनमानस के लिए प्रेरणा का स्त्रोत है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को आ ान किया कि वे भगवान श्रीराम के आदर्शों को जीवन में आत्मसात करते हुए देश एवं समाज की उन्नति में अपना योगदान देने का संकल्प लें।